वैश्विक महामारी से प्रभावित अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में भारत की भूमिका : चुनौतियाँ एवं संभावनाएँ

डॉ0 नीलिमा सिंह
एसोसिएट प्रोफेसर, राजनीतिशास्त्र विभाग
राजर्षि टण्डन महिला महाविद्यालय
(संघटक इलाहाबाद विश्वविद्यालय), प्रयागराज, उ0प्र0
Email: neelimasingh.96@gmail.com

सारांश

दिसम्बर, 2019 में उत्पन्न कोविड–19 महामारी ने थोड़े ही समय में विश्व को अपनी चपेट में ले लिया जिसके कारण जन व धन की हानि हुई। चीन के वुहान शहर में पहला मामला चिन्हित हुआ और विश्व के अनेक देश चीन को सन्देह की दृष्टि से देखने लगे तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इसे फरवरी में महामारी घोषित किया जिसके कारण इस अन्तर्राष्ट्रीय संगठन की भूमिका भी संदेह के घेरे में आ गई। विश्व के अनेक देश अपने उद्योग–धन्धों को चीन से बाहर लाने की सोचने लगे। चीन व अमरीका के मध्य आरोपों प्रत्यारोपों का दौर प्रारम्भ हुआ और अनेक देश भारत की प्रभावी भूमिका की अपेक्षा करने लगे। आर्थिक व्यवस्था के गिरते स्तर, अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में महाशक्तियों चीन व अमरीका के बीच पारस्परिक अविश्वास तथा भारत का इस परिस्थिति में भी संतुलित व्यवहार और मानवीय आधार पर पड़ोसी देशों की सहायता से लेकर विश्व के पचास से अधिक देशों को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन व पैरासीटामॉल उपलब्ध कराना, ऐसे कारक हैं जो यह सोचने को बाध्य करते हैं कि क्या भारत वैश्विक महामारी से प्रभावित अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रभावी भूमिका निभा सकता है? भारत की प्रभावी भूमिका के मार्ग में क्या चुनौतियाँ एवं संभावनाएं हैं? इन प्रश्नों का प्रस्तुत प्रपत्र में विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है।

मुख्य शब्दः *कोविड–19, विश्व स्वास्थ्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, लॉक डाउन, मेडिकल डिप्लोमेसी।*

प्रस्तावना

कोविड–19 संकट दिसम्बर 2019 में उत्पन्न वह संकट है जिसने कुछ महीनों में सम्पूर्ण विश्व के लगभग सभी देशों को अपनी चपेट में लिया है और इसके कारण न केवल धन व जन की हानि हुई है वरन् अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में भी नई समीकरणों, शीर्ष नेतृत्व व शक्ति पर भी पूर्वानुमान लगाये जाने लगे हैं और विश्लेषण किया जा रहा है। कोविड संकट के समय अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों की निष्प्रभावी भूमिका और विश्व की दो प्रमुख शक्तियों चीन व अमरीका

के बीच आरोपों एवं प्रत्यारोपों ने भूमण्डलीकरण के पराभव की भी भविष्यवाणी होने लगी है। इसी पृष्ठभूमि में हम इस महामारी के समय व बाद में अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में भारत की भूमिका प्रभावी होगी या नहीं अथवा भारत की प्रभावी भूमिका की क्या संभावनाएँ और चुनौतियाँ हैं, इस पर विचार करेंगे।

कोविड–19 संकट के समय दो महत्वपूर्ण समस्यायें या संकट सामने उभर कर आये हैं– पहला अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों की वैधानिकता में उत्तरोत्तर गिरवट आई है और दूसरा वैश्विक संकट का संबंध राष्ट्रीय संप्रभुता से है।[1] आज विश्व मंच पर हर राष्ट्र अपनी संप्रभुता को उग्र तरीके से प्रस्तुत कर रहा है।

सर्वप्रथम हम बात करें अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के उत्तरोत्तर निष्प्रभावी होने की तो कोविड–19 संकट के समय सबसे ज्यादा प्रश्न चिन्ह विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) पर लगा है। यदि यह संगठन उचित रीति से कार्य कर रहा होता तो विश्व को नये कोरोना वायरस को समझने में इतना विलम्ब नहीं होता। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पहले तो चीन के कथनों और दावों पर लचीला रवैया अपनाया और कोविड–19 को महामारी घोषित करने में काफी विलम्ब किया और 11 मार्च 2020 को इसे महामारी घोषित किया। तब तक पूरे विश्व में तबाही प्रारम्भ हो चुकी थी। संयुक्त राज्य अमरीका ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के चीन के प्रभाव में काम करने का आरोप लगाया तथा उसकी निष्पक्ष भूमिका न निभाने के विरोध में विश्व स्वास्थ्य संगठन को 500 मिलियन डॉलर की सहायता राशिप्रदान करने पर रोक लगा दी और अब डोनाल्ड ट्रंप ने विश्व स्वास्थ्य संगठन को 30 दिन के अन्दर चीन के शिकंजे से बाहर न निकलने पर इसकी फंडिग हमेशा के लिए रोकने की धमकी दी है और उसकी सदस्यता से हटने पर भी विचार करने की संभावना व्यक्त की है।[2] वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन की वार्षिक बैठक में 100 सदस्यों की सहमति से विश्व स्वास्थ्य संगठन की भूमिका की जाँच तथा कोरोना वायरस की उत्पत्ति सम्बन्धी जाँच के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया है।[3]

दूसरा संगठन है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) जिसका मूल उद्देश्य विश्व में शान्ति व सुरक्षा स्थापित करना है परन्तु ऐसा नहीं है कि स्वास्थ्य संकट के समय इसने अपनी भूमिका नहीं निभायी है। वर्ष 2000 में सर्वप्रथम एच.आई.वी. / एड्स के कारण उत्पन्न संकट अफ्रीका में शान्ति व सुरक्षा के लिए इसने प्रस्ताव पारित किया और फिर वर्ष 2014 में इबोला संकट के समय भी इसने अपनी भूमिका निभाई परन्तु कोविड–19 के समय यह निष्क्रिय रहा। यूरोपियन यूनियन कोविड संकट के समय अपने सदस्य राष्ट्रों को सहायता पहुँचाने में अक्षम रहा और इसका फायदा उठाते हुए चीन वहाँ तक पहुँच गया। विश्व व्यापार संगठन (WTO) पर क्रमशः संकट के बादल छा रहे हैं। अमरीका की अमेरिकन फर्स्ट नीति से इसका प्रारम्भ हो चुका है। विश्व व्यापार संगठन की ट्रंप ने आलोचना करते हुए कहा था कि यह चीन के प्रभाव में काम कर रहा है। यह संस्था चीन को एक विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में परिभाषित करती है जबकि अमरीका को एक विकसित देश के रूप में मानती है। चीन विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में बड़ा फायदा उठा रहा है।

इस पृष्ठभूमि में देखा जाये तो भारत के पास अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रभावी भूमिका निभाने के अवसर हैं और कहा भी गया है कि कठिन समय चुनौतियाँ लेकर आता है और उसे अवसर में बदलना हमारी सफलता है। परन्तु ऐसा नहीं है कि कोविड संकट के बाद भारत बड़ी सरलता से वैश्विक राजनीति में अपना शीर्ष स्थान बनाने में सफल होगा। भारत की अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रभावी भूमिका की चर्चा के पीछे भारत की विगत कुछ वर्षों में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रभावी भूमिका है और यही कारण है कि राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए सर्वप्रथम प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में अपने पड़ोसी देशों को अपने विश्वास में लेने का प्रयास किया। चीन से सम्बन्धों के उतार चढ़ाव के बावजूद अनेक महत्वपूर्ण समझौते किये, अमरीका से अनेक क्षेत्रों में सहयोग संधि की तथा अरब देशों से भी मित्रवत् सम्बन्ध स्थापित किये। जबकि पूर्व में धार्मिक आस्था के कारण इन राष्ट्रों का पाकिस्तान के प्रति अधिक झुकाव था। 57 मुस्लिम देशों के संगठन (Organisation of Islamic Countries) जो मुस्लिम राष्ट्रों की सामूहिक आवाज है ने वर्ष 2019 में अपनी बैठक में भारत को आमंत्रित किया जो 50 वर्षों में पहली बार हुआ। यही कारण था कि भारत में अनुच्छेद 370 के हटने पर पाकिस्तानी प्रलाप हो या विंग कमांडर अभिनंदन की सकुशल वापसी हो, कुलदीप जाधव केस हो अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को राष्ट्रों का मौन अथवा खुला समर्थन मिला है।

अब कोविड–19 संकट के समय भी भारत कूटनीतिक रूप से सक्रिय रहा है। 11 मार्च को कोविड–19 महामारी घोषित होते ही प्रधानमंत्री ने विदेश मंत्री के साथ विश्व के अनेक नेताओं और राष्ट्रध्यक्षों से बात की। सार्क देशों के शासनाध्यक्षों, G20 के नेताओं और गुटनिरपेक्ष आन्दोलन की क्रांफ्रेस में ऑन लाईन सम्मिलित हुए। सार्क देशों से 13 मार्च, 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने साझा कार्य योजना बनाने की बात कही और अनुमान अनुसार पाकिस्तान को छोड़कर सभी देशों ने इसका समर्थन किया। पाकिस्तान व श्रीलंका OBOR-BRI के कारण चीन के प्रभाव में हैं और सामरिक दृष्टि से पाकिस्तान सदैव चीन को प्राथमिकता देता है और इसीलिए उसने वुहान से अपने नागरिकों को वापस लाने तक का प्रयास नहीं किया। चीन की मेडिकल सहायता, टेस्ट किट व अन्य सहयोग के माध्यम से दक्षिण एशिया में अपनी प्रभुता को स्थापित करने के प्रयास को भारत ने बड़ी चतुराई से विफल किया और मालदीव व नेपाल में न केवल क्वारंटीन सेन्टर बनाने में सहयोग किया वरन् सार्क कोविड फंड में 10 मिलियन अमरीकी डालर का योगदान दिया तथा दो नौसैनिक बेड़े आवश्यकता पड़ने पर भेजने के लिए तैयार रखे। प्रधानमंत्री मोदी का आह्वान था कि हमारे पड़ोसी देशों का पारस्परिक सहयोग विश्व के लिए आदर्श होना चाहिए।[4]

कोविड संकट के समय चीन ने लाभ कमाने की मंशा से अनेक देशों को सहयोग के नाम पर खराब गुणवत्ता के उपकरण व स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध करवाई। महामारी का स्रोत चीन का वुहान शहर ही था अतः विश्व के अनेक देश चीन को आशंका की नजर से देख रहे थे और देख रहे हैं।[5] ऐसे में भारत ने मेडिकल डिप्लोमेसी के तहत अमरीका सहित अनेक देशों को संकट के समय हाइड्राक्सीक्लोरोक्वीन एवं पैरासिटामॉल निर्यात कर मानवता का बड़ा संदेश दिया।

भारत की बड़ी जनसंख्या की तुलना में संक्रमित मामलों की कमी व अन्य देशों की तुलना में मृत्यु दर की कमी ने भारत की ओर विश्व के अनेक नेताओं को देखने के लिए मजबूर किया है।

भारत वर्तमान में ऐसी स्थिति में है कि वह चीन व अमरीका दोनों देशों से समान रूप से सम्बन्धों को राष्ट्रहित के अनुरूप स्थापित कर सकता है। कोविड संकट ऐसा संकट है जिसमें उच्च प्रतिरोधक क्षमता वाले लोगों के स्वस्थ रहने की संभावना रहती है। भारत की प्राचीन परंपरा में निहित योग व आर्युवेद की अवधारणा इस समय रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में बहुत सहायक है। 21 जून, 2015 से भारत में योग दिवस मनाने का प्रारम्भ हुआ और आज विश्व में अनेक देशों में योग के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है और योग के पूरक के रूप में भारत में प्रचीन काल से चली आ रही आर्युवेदिक चिकित्सा पद्धति कोविड संकट के समय प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में प्रभावी है, इन दोनों को भारत विश्व स्तर पर स्थापित करने में सफल हो सकता है। भारतीय जीवन शैली नमस्ते, स्वच्छता, बाहर के कपड़े, वस्तु, चप्पल, जूते आदि घर में अन्दर नहीं आने चाहिए, यह सब अब वैज्ञानिक भी स्वीकार कर रहे हैं।

संकट की इस घड़ी में जब दुनिया की तमाम वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में मंदी जारी है और परिणामस्वरूप शेयर मार्केट में गिरावट की निरन्तरता है, शेयर वैल्यू कम हो रही हे, ऐसी स्थिति का लाभ उठाकर चीन दुनिया के विभिन्न देशों में उनके बैंकिंग और उनकी कम्पनियों में हिस्सेदारी हासिल करने की कोशिश कर रहा है। भारत में HDFC बैंक में चीन के पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना ने 1% हिस्सेदारी ली है। अतः भारत सरकार ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए FDI नीति में बदलाव किया और अब आटोमेटिक रूट के जरिए आने वाले किसी भी FDI के लिए सरकार की अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया है।[6] जहाँ तक प्रश्न बिगड़ी हुई अर्थव्यवस्था का है तो भारत के विभिन्न शक्तियों सहित अनेक विकासशील देशों से अच्छे सम्बन्ध है और वह अपने दीर्घ योजना सम्बन्धों के आधार पर अपनी स्थिति में सुधार कर सकता है। भारत विश्व को पारस्परिक सहयोग और बहुपक्षी शक्ति केन्द्रों से सम्बन्धों के आधार पर विश्व को नई दिशा दे सकता है।

कोविड–19 के खिलाफ लड़ाई में मोदी को घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भले समर्थन हासिल हो लेकिन देश की खस्ता हाल मेडिकल सुविधाएं और आर्थिक मुश्किलों की शुरूआत उनके सामने बड़ी चुनौतियाँ हैं। परन्तु यह सब इतना सरल नहीं है। इसके लिए सर्वप्रथम भारत को आन्तरिक स्तर पर अपने हालातों को सुधारना होगा। अर्थव्यवस्था को सुधारना होगा और चीन में अविश्वास के कारण बाहर जा रही कम्पनियों को भारत में प्रवेश दिलाने के लिए प्रयास करना होगा लेकिन उसे पहले अपने हितों और अपनी शर्तों को साधना होगा।

भारत में स्वास्थ्य सेवा मानकों के अनुरूप नहीं है। भारत सरकार ने नवम्बर 2019 में संसद में बताया था कि देश भर में प्रति 1445 लोगों पर एक डॉक्टर उपलब्ध है जोकि विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानक प्रति हजार लोगों पर एक डॉक्टर से कम है।[7] स्वास्थ्य के क्षेत्र में विगत कुछ वर्षों से भारत में निजी क्षेत्र को बढ़ावा मिल रहा था और सरकारी क्षेत्र उपेक्षित थे परन्तु कोविड–19 संकट के समय इन्हीं सरकारी क्षेत्रों ने आगे बढ़कर ज्यादा सहयोग किया है और

भारत को स्वास्थ्य सेवा में सुधार करने के लिए इस दिशा में सोचना होगा। मंगलवार को हुई अमरीकी स्वास्थ्य विभाग की घोषणा के अनुसार भारत अमरीका कोविड–19 वैक्सीन रिसर्च व ट्रयल पर पारस्परिक सहयोग करेंगे। भारत की छः कम्पनियाँ शोध कार्य में लगी हैं और इस दिशा में सफलता भारत को एक नई दिशा प्रदान करेगी। यदि भारत सस्ती वैक्सीन का निर्माण करने में सफल होता है तो निश्चित ही यह विश्व को नेतृत्व प्रदान करने में अग्रसर करेगा।

भारत में कोविड–19 महामारी के कारण लॉकडाउन की घोषणा की गई और उसमें सबसे प्रभावित श्रमिक वर्ग हैं जो पलायन को मजबूर हैं। इस समस्या के कई स्वरूप सामने आये और विभिनन दलों द्वारा इस पर राजनीति भी की जा रही है। मजदूरों की समस्या को केवल कोविड–19 से जोड़कर नहीं देखा जा सकता है। भारत में श्रमिक संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में कार्य करते हैं और लॉकडाउन का प्रभाव असंगठित क्षेत्रों पर अधिक पड़ा है। सरकार चाहे राज्य हो या केन्द्र के पास इन श्रमिकों के सम्बन्ध में कोई ठोस आँकड़े नहीं हैं। अधिक जनसंख्या, स्थानीय स्तर पर रोजगार की कमी, विकेन्द्रित विकास के अभाव में मजदूरों की स्थिति दयनीय हो गयी है और विचारधारा विभेद और दल विभेद के कारण विभिन्न राज्य सरकारों और राजनीतिक दलों ने इन्हें मोहरा बनाया है। आने वाले समय में करोड़ों की संख्या में लोग बेरोजगार होंगे और जब तक भारत अपनी इस आन्तरिक समस्या को नहीं सुधारता तब तक उसके वैष्विक स्तर पर भूमिका निभाने पर प्रश्नचिन्ह लग जाता है।

लोकतंत्र में मीडिया को चतुर्थ स्तम्भ कहा गया है परन्तु मीडिया सुदृढ़ता प्रदान करने के स्थान पर भ्रामक/पक्षपाती समाचार फैलाने में अग्रणी है। मीडिया वॉच डॉग की जगह कार्पोरेट का रोल निभा रही है और लाभ की आकांक्षा में मीडिया क्षेत्र में नैतिक मूल्यों का पतन हो रहा है। विश्व के सर्वाधिक बड़े मीडिया तंत्र भारत में है जिसका स्वामित्व कुछ थोड़े ही हाथों में केन्द्रित है और इसमें विदेशी पूंजी भी लगी है। पूंजी निवेश का उद्देश्य येन केन प्रकारेण मात्र लाभ कमाना होता है। अतः उनसे निष्पक्षता, राष्ट्रहित के प्रति निष्ठा की अपेक्षा करना निरर्थक है। भारत को अभिव्यक्ति की आजादी के अन्तर्गत मिली प्रेस की स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखते हुए इसके नियमन की भी आवश्यकता है। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से भारत की छवि को कुछ कट्टरपंथी जो आघात करने का प्रयास करते हैं वह भारत की वैश्विक स्थिति को मजबूत करने के प्रयासों पर कुठाराघात होता है। पाकिस्तान तो सदैव ही द्विपक्षीय मामलों को अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर उठाने का प्रयास करता रहा है परन्तु कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी अपने कुत्सित प्रयासों से भारत की छवि को आघात पहुँचाने में अपनी भूमिका निभाते हैं। अनेक बार ऐसे उदाहरण सामने आये हैं जब विपक्षी दल के नेताओं के कथन को आधार बनाकर पाकिस्तान ने अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को घेरने का प्रयास किया गया है। लोकतंत्र की खूबसूरती विचार विभिन्नताओं की उपस्थिति में है परन्तु आवश्यकता और संकट के समय इसमें एकता का भाव होना भी उतना ही आवश्यक है परन्तु दुख का विषय है कि कई बार ऐसा नहीं हो पाया है।

किसी भी राष्ट्र की उन्नति उसके नागरिकों की निष्ठा एवं कर्तव्य परायणता पर भी निर्भर

करती है। भारत में राज्य से नागरिकों को अधिकारों की अपेक्षा ज्यादा है और कर्तव्यों के प्रति उनमें उदासीनता है। देश की हर समस्या का समाधान दूसरे देश के उदाहरण के रूप में नहीं किया जा सकता क्योंकि प्रत्येक देश की राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक मूल्य अलग–अलग होते हैं और भारत में भी ऐसा ही है। उसे अपनी देश की संसाधनों की तुलना में बढ़ती जनसंख्या पर रोक लगाने, सतत् और विकेन्द्रिकृत विकास की ओर ध्यान देना होगा।

अन्त में निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि कोविड–19 के समय अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रति बढ़ता अविश्वास, चीन–अमरीका की आपसी नूराशक्ति के समय भारत के पास अवसर है कि विगत कुछ वर्षों में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उसने अपनी जो छवि बनाई है उसको उत्तरोत्तर शीर्ष पर ले जाने का प्रयास करे। विश्व के समक्ष अति वैश्वीकरण और बाजारीकरण ने पराश्रितता के दुष्परिणाम को देख लिया। अतः भारत को इस संकट के समय सामने आई कमजोरियों को दूर कर आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करना होगा, सतत विकास पर ध्यान देना होगा और सबसे पहले अपने आन्तरिक हालात को सुधारना होगा। भारत वसुधैव कुटुम्बकम की धारणा वाला देश है अतः परिवार के समान सहयोग व प्रेम बाँटना इसका जीवन मूल्य है और आदर्श सहयोग, नैतिकता का सन्देश देकर वह नेतृत्व प्रदान करने का कार्य कर सकता है। राजनीतिक विविधताओं के समीकरणों के बीच वह अपनी भूमिका बहुत अच्छे तरीके से निभा सकता है। प्रशासनिक चुनौती को स्वीकार करते हुए भारत के सामने अवसर है कि वह विकासवादी शक्ति के रूप में एशिया व अफ्रीका महाद्वीप के करोड़ों लोगों के विकास की जरूरतों को प्रशासनिक समाधान उपलब्ध कराके बिल्कुल अलग तरीके से विश्व शक्ति के तौर पर उभरने का प्रयास करे। परन्तु सबसे पहले उसे अपने देश की जान व जहान पर आसन्न संकट को दूर करना होगा।

सन्दर्भ ग्रंथ

1. शशि थरूर एवं समीर सरन, orfoline.org/hindi/research/covid19 अप्रैल 8, 2020
2. अमर उजाला 20 मई, 2020 पृ0 12
3. अमर उजाला 20 मई, 2020 पृ0 12
4. V.K. Chaturvedi - What the new World order will look like Post Covid-19, April 20, 2020 -http://www.firstpost.com.India
5- Sujan R. Chinoy - India can absorb Shocks of pandemic, take the lead in reshaping global order, May 4, 2020, indianexpress.com
6. विक्रान्त सिंह एवं अखिल पाण्डेय, फाइनैंस एण्ड इकनामिकल थिंक काउंसिल, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय
7. सचिन गोगोई – कोरोना वायरस : *भारतीय राजनीति को कैसे प्रभावित कर रही है?*, 12 अप्रैल, 2020, bbc.com